



## एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट

### प्रलिस के लिये:

[एक राष्ट्र, एक चुनाव, नगर पालिकाएँ और पंचायतें, भारत का चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, अनुच्छेद 356](#)

### मेन्स के लिये:

एक साथ चुनाव, महत्त्व और चुनौतियाँ

स्रोत: [पी.आई.बी.](#)

### चर्चा में क्यों?

चुनाव सुधार की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोव्दि की अध्यक्षता में गठित [एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति](#) ने भारत में [लोकसभा](#), राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिये एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट इस महत्त्वपूर्ण बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिये संविधान में व्यापक सफारिशों और संशोधनों की रूपरेखा तैयार करती है।

### एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सफारिशें क्या हैं?

- एक साथ चुनाव के लिये संक्रमण:**
  - अनुच्छेद 82A में संशोधन:**
    - समिति राष्ट्रपति को लोकसभा और विधान सभाओं के एक साथ चुनाव शुरू करने के लिये "नयित तारीख" निर्दिष्ट करने का अधिकार देने के लिये **संविधान के अनुच्छेद 82A** में संशोधन करने का सुझाव देती है।
    - इस तारीख के बाद जनि राज्य विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, वे एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिये अपनी शर्तों को संसद के साथ समन्वयति कर लेंगी।
  - अवधि समन्वयन (Term Synchronization):**
    - यदि **वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों** के बाद सफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है और लागू किया जाता है, तो संभवतः पहला एक साथ चुनाव वर्ष 2029 में हो सकता है।
      - वैकल्पिक रूप से यदि वर्ष 2034 के चुनावों को लक्ष्यति किया जाता है, तो वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद नयित तारीख की पहचान की जाएगी।
    - जनि राज्यों में **जून 2024 और मई 2029** के बीच चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल **18वीं लोकसभा** के साथ समाप्त हो जाएगा, भले ही इसके **परिणामस्वरूप कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार के उपाय के रूप में पाँच साल से कम हो**।
      - पश्चिमि बंगाल, तमलिनाडु (2026), पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (2027) और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना (2028) जैसे राज्य अपने चुनावी चक्र को समन्वयति (synchronise) करेंगे।
    - वर्ष 2024 के चुनावों के बाद चुनी गई सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2029 या 2034 को लक्ष्य करते हुए एक साथ चुनाव लागू करने के लिये शुरुआती बटु तय करेगी।
    - संसद या राज्य विधानसभा के समय से **पहले भंग होने की स्थिति में समन्वय बनाए रखने के लिये, समिति ने एक साथ चुनावों के अगले चक्र तक केवल शेष कार्यकाल या "असमाप्त अवधि (unexpired term)"** के लिये नए चुनाव कराने की सफारिश की।
      - यह उपाय सुनिश्चित करता है कि कोई भी त्रिशंकु सदन या [अवशिवास प्रस्ताव](#) एक साथ चुनावों की समग्र समय-सीमा को प्रभावति नहीं करता है।
  - स्थानीय निकाय चुनावों का समन्वयन:**
    - संसद को आम चुनावों के साथ [नगर पालिकाओं और पंचायतों](#) के चुनावों का समन्वय सुनिश्चित करने के लिये संभवतः **अनुच्छेद 324A की शुरुआत** के माध्यम से कानून बनाने की सलाह दी जाती है।

- यह कानून स्थानीय निकायों की शर्तों को निर्धारित करेगा और उनके चुनाव कार्यक्रम को राष्ट्रीय चुनावी समय-सीमा के साथ संरेखित करेगा।
- **मतदाता सूची तैयार करना एवं प्रबंधन:**
  - **समिति संवधान के अनुच्छेद 325** में संशोधन करने का सुझाव देती है ताकि भारत के **चुनाव आयोग** को **राज्य चुनाव आयोगों (SECs)** के परामर्श से सरकार के सभी स्तरों पर लागू एकल **मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान-पत्र** तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके।
    - लोकसभा के लिये मतदाता सूची ECI द्वारा तैयार और रखरखाव की जाती है, जबकि स्थानीय निकायों के लिये मतदाता सूची SEC द्वारा तैयार की जाती है।
    - समिति पुनर्रमतदान को रोकने और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा के लिये ECI तथा **राज्य चुनाव आयोगों** के बीच सामंजस्य के महत्त्व पर जोर देती है।
- **लॉजिस्टिक व्यवस्थाएँ और व्यय अनुमान:**
  - समिति ECI से एक साथ चुनावों के लिये **वसित्तृत आवश्यकताएँ और व्यय अनुमान प्रस्तुत** करने को कहती है।
  - नरिबाध लॉजिस्टिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये समिति ECI और SECs से व्यापक योजनाएँ तथा अनुमान विकसित करने का आग्रह करती है।
    - इन योजनाओं में उपकरण की आवश्यकताएँ, कर्मियों की तैनाती और सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये।
- **शासन और विकास पर प्रभाव:**
  - समिति प्रभावी नरिण्य लेने और सतत् विकास के लिये शासन में नश्चितता के महत्त्व को रेखांकित करती है।
  - यह नीतगित पंगुता को रोकने और प्रगत के लिये अनुकूल वातावरण को बढावा देने में समकालिक चुनावों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

## एक साथ चुनाव के संबंध में वविाद क्या हैं?

- **पक्ष में तरक:**
  - **लागत कषमता:**
    - एक साथ चुनाव कराने से राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा कयि जाने वाले **पर्याप्त आवरती व्यय में कमी आती है।**
    - चुनावों को **एक कार्यक्रम में समेकित करने से मतदाता पंजीकरण, मतदान केंद्र, चुनाव कर्मचारी, सुरक्षा तैनाती** और अन्य लॉजिस्टिक संबंधी आवश्यकताओं से जुड़ी लागत कम हो जाती है।
    - सभी चुनावों के लिये एक ही मतदाता सूची के साथ, सुरक्षा बलों और नागरिक अधिकारियों जैसे प्रशासनिक संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कयि जाता है, जसिसे सार्वजनिक धन की बचत होती है जसिसे अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये पुनर्रनिदेशित कयि जा सकता है।
  - **उन्नत शासन एवं प्रशासन:**
    - एक साथ चुनाव होने से चुनावी प्रक्रया सुव्यवस्थित हो जाती है, जसिसे बार-बार होने वाले चुनावों के कारण **शासन और प्रशासन पर पडने वाला दबाव कम** हो जाता है।
      - अलग-अलग चुनावों के दौरान सुरक्षा और पुलिस बलों की लंबे समय तक तैनाती **राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून परवरतन परयासों पर दबाव डाल सकती है**, जसिसे एक साथ चुनाव कराकर कम कयि जा सकता है।
    - **अधिकारियों के बडे पैमाने पर तबादले और अलग-अलग चुनावों के दौरान आचार संहिता** के कारण होने वाला व्यवधान सरकारी मशीनरी के सुचारु कामकाज में बाधा डाल सकता है, जसिसे समकालिक चुनावों के माध्यम से कम कयि जा सकता है।
  - **राजनीति में धन का प्रभाव कम होना:**
    - एक साथ चुनाव कराने से **चुनाव अभयानों** की आवृत्ति और संबंधित खर्चों को कम करके राजनीति में धन की भूमिका को कम कयि जा सकता है।
      - अभयान वलित नयियों को ECI द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से लागू कयि जा सकता है, जसिसे सभी दलों और उम्मीदवारों के लिये समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
  - **वभाजनकारी राजनीति का शमन:**
    - **'एक राष्ट्र-एक चुनाव'** की अवधारणा का उद्देश्य मतदाताओं को एकजुट करने में कषेत्रवाद, जातविाद और सांप्रदायिकता के वभाजनकारी प्रभाव को कम करना है।
      - राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और एकीकृत चुनावी एजेंडे को बढावा देकर, एक साथ चुनाव संकीर्ण हतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढावा देने में मदद कर सकते हैं।
  - **मतदाता सहभागिता में वृद्धि:**
    - वभिन्न स्तरों पर बार-बार होने वाले चुनावों से उत्पन्न होने वाली **वोटर फेटीग** को एक ही कार्यक्रम में एकत्रित करके कम कयि जा सकता है।
    - एक साथ **चुनाव मतदाताओं की उदासीनता को कम करके और प्रत्येक चुनावी अभ्यास** के महत्त्व को बढाकर संभावित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मतदान प्रतशित बढा सकते हैं।
- **एक साथ चुनाव के खलिाफ तरक:**
  - **संघवाद और कषेत्रीय प्रतनिधित्व:**
    - एक साथ चुनाव, चुनावी प्रक्रया को केंद्रीकृत करके और संभावित रूप से राष्ट्रीय मुद्दों के साथ कषेत्रीय तथा स्थानीय मुद्दों को प्रभावित करके **संघवाद** के सिद्धांतों को कमजोर कर सकते हैं।
      - घटक राज्य, **वशिष रूप से वे जो राष्ट्रीय स्तर पर गैर-प्रमुख दलों द्वारा शासित हैं**, समकालिक चुनाव परदृश्य में हाशिए पर या अपर्याप्त प्रतनिधित्व महसूस कर सकते हैं।
      - संवधान में नहिित संघीय भावना को कमजोर करते हुए, राष्ट्रीय पार्टियाँ कषेत्रीय पार्टियों पर अनुचित लाभ प्राप्त कर

सकती हैं।

- **लागत नहितारथः**
  - एक साथ चुनावों के कार्यान्वयन के लिये अतिरिक्त **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन** और **मतदाता सत्यापति पेपर ऑडिट ट्रेल** की खरीद में महत्वपूर्ण नविश की आवश्यकता होगी, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।
  - वधान परिषदों/राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों और उप-चुनावों के लिये अभी भी अलग-अलग मतदान आयोजनों की आवश्यकता होगी, जो समकालिक चुनावों के बावजूद चल रही लागत में योगदान देगा।
- **जवाबदेही और प्रतिनिधित्व पर प्रभावः**
  - सरकार के विभिन्न स्तरों पर बार-बार चुनाव होने से **निरिवाचिता प्रतिनिधियों के बीच जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलती है और मतदाताओं** को अपनी प्राथमिकताएँ व्यक्त करने के नियमित अवसर सुनिश्चित होते हैं।
    - चुनावों को समकालिक करने से **चुनावी जवाबदेही जाँच की आवृत्त कम हो सकती है** और निरिवाचिता अधिकारियों की अपने मतदाताओं की बढ़ती आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही सीमिति हो सकती है।
- **आवश्यक संवैधानिक संशोधनः**
  - भारत का संसदीय लोकतंत्र लोकसभा और राज्य वधानसभाओं को उनके पाँच वर्ष के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने की अनुमति देता है।
    - सभी सदनों के लिये पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल अवधि और वधितन से संबंधित **अनुच्छेद 83, 85, 172 तथा 174 में संवैधानिक संशोधन** की आवश्यकता है।
    - एक साथ चुनावों को समायोजित करने के लिये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने को न्यतिरति करने वाले अनुच्छेद 356 में संशोधन की भी आवश्यकता होगी।
- **सुरक्षा नहितारथः**
  - एक साथ चुनावों के दौरान, **चुनाव ड्यूटी के लिये बड़े सुरक्षा बलों को तैनात** करना संभावित रूप से **राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर कर** सकता है, क्योंकि यह उन्हें सीमा सुरक्षा से वधिलति कर देता है।

## एक साथ चुनाव के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

संवैधानिक प्रावधान	वधिरण
<b>अनुच्छेद 83</b>	लोकसभा (लोगों का सदन) की अवधि निरिदषिट करती है, जिसमें कहा गया है, कि यह अपनी पहली बैठक से पाँच वर्ष तक जारी रहेगी जब तक कि पहले भंग न हो जाए।
<b>अनुच्छेद 172</b>	राज्य वधान सभाओं की अवधि से संबंधित, यह घोषणा करते हुए कि एक वधान सभा अपनी <b>पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष तक जारी रहेगी।</b>
<b>अनुच्छेद 324</b>	निरिवाचन आयोग को मतदाता सूची की तैयारी और <b>संसद</b> , राज्य वधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों की निगरानी, निरिदेशन एवं न्यतिरण करने के लिये सशक्त बनाना।
<b>अनुच्छेद 356</b>	संवैधानिक शासन की वधिलता के मामले में किसी राज्य में <b>राष्ट्रपति शासन</b> लगाने की अनुमति देता है, जिससे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जाता है।
<b>लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951</b>	भारत में चुनाव कराने के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें मतदाता सूची, सदस्यता के लिये योग्यता और चुनाव आचरण जैसे पहलू शामिल हैं।

## भारत में एक साथ चुनाव का इतिहास

- भारत में एक साथ चुनाव, जहाँ लोकसभा तथा राज्य वधानसभाएँ दोनों एक साथ निरिवाचिता होते थे, आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में **1952, 1957 एवं 1962** में प्रचलित थे।
  - हालाँकि, राजनीतिक अस्थिरता, राज्य वधानसभाओं के शीघ्र वधितन और कषेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिये अलग-अलग चुनावों की आवश्यकता जैसे विभिन्न कारणों के कारण, एक साथ चुनावों की प्रथा धीरे-धीरे खत्म हो गई।
- वर्ष 2019 में, **केवल चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सकिक्मि)** में लोकसभा के साथ वधानसभा चुनाव हुए।

## एक साथ/समकालिक चुनाव वाले देश

- **दक्षिण अफ्रीका:**
  - नेशनल असेंबली और प्रांतीय वधानसभाओं के चुनाव हर 5 वर्ष में एक साथ होते हैं।
  - दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल असेंबली द्वारा किया जाता है।
- **स्वीडन:**
  - स्वीडन के प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्येक चार वर्ष में वधियायिका द्वारा किया जाता है।
- **जर्मनी:**
  - जर्मनी के चांसलर का चुनाव प्रत्येक चार वर्ष में वधियायिका द्वारा किया जाता है।
  - चांसलर में वधिवास की कमी को केवल उत्तराधिकारी चुनकर ही दूर किया जा सकता है।

#### ■ ब्रिटन:

- ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता तथा पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये नश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि पहला चुनाव 7 मई, 2015 को और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष मई के पहले गुरुवार को होगा।

## एक साथ/समकालिक चुनाव के संबंध में विभिन्न अन्य सफारिशें क्या हैं?

#### ■ पछिली रिपोर्ट:

- एक साथ/समकालिक चुनाव के मुद्दे को **वधि आयोग (1999)** और **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति (2015)** की रिपोर्टों में हल किया गया है। इसके अतिरिक्त, वधि आयोग ने वर्ष 2018 में एक प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की।

#### ■ सफारिशों का सारांश:

##### ○ क्लबिंग चुनाव:

- प्रस्तावों में लोकसभा चुनावों को लगभग आधे राज्य विधानसभा चुनावों के साथ एक चक्र में जोड़ने का सुझाव दिया गया है, जबकि शेष राज्य विधानसभा चुनावों को ढाई वर्ष बाद दूसरे चक्र में कराने का सुझाव दिया गया है।
- इसके लिये मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल को समायोजित करने हेतु संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन की आवश्यकता होगी।

##### ○ अवशिष्ट प्रस्ताव:

- लोकसभा या विधानसभा में किसी भी अवशिष्ट प्रस्ताव के साथ वैकल्पिक सरकार बनाने का विश्वास प्रस्ताव भी होना चाहिये।
- यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा का विघटन अपरहिर्य है, तो नवगठित सदन को विघटन को हतोत्साहित और वैकल्पिक सरकार बनाने की खोज को प्रोत्साहित करने के लिये मूल सदन की केवल शेष अवधि में ही काम करना चाहिये।

##### ○ उप-चुनाव:

- सदस्यों की मृत्यु, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण होने वाले उपचुनावों को दक्षता के लिये एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है और वर्ष में एक बार आयोजित किया जा सकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### ??????????:

#### प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो मतदान के लिये योग्य है, किसी राज्य में छह माह के लिये मंत्री बनाया जा सकता है तब भी, जब कबिह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो दांडक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे पाँच वर्ष के लिये कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिये स्थायी तौर पर नरिहत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो।

#### उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

#### उत्तर: (d)

#### प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों को हल करता है।

#### उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

**??????:**

प्रश्न. "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमिति कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।" (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/high-level-committee-report-on-simultaneous-elections>

